

प्रेषक,
हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषय:-प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की भूमि पर पट्टेदारों एवं अध्यासियों के अधिकारों को विनियमित किये जाने विषयक।

महोदय,

शासन द्वारा वर्ष 2016 में निर्गत निम्नांकित तालिका में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा विभिन्न श्रेणी की भूमि पर पट्टेदारों व अध्यासियों के अधिकारों को विनियमित करते हुए संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया था, सम्प्रति उक्त शासनादेशों के प्रभावी रहने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	निर्धारित समयावधि
1.	प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या-804/XVIII(II)/2016-07(46)/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया है।	दिनांक 17 जुलाई, 2017 तक
2.	प्रदेश में वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान करते हुए विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या-426/XVIII(3)/2016-20(25)/2012 दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया है।	दिनांक 21 जुलाई, 2017 तक
3.	जनपद नैनीताल के नगर पंचायत क्षेत्र लालकुआं में अवैध कब्जेधारकों/पट्टेधारकों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या-425/XVIII(3)/2016-20(25)/2012 दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया है।	दिनांक 21 जुलाई, 2017 तक
4.	गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिये गये भूमि पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या-1767/XVIII(II)/2016-02(01)/2016 दिनांक 27 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया है।	दिनांक 26 जुलाई, 2017 तक

2- उक्त शासनादेशों की प्रभाव अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-1 में व्यक्त समस्त शासनादेशों के अनुसार निम्न संशोधनों/शर्तों के साथ विनियमितीकरण हेतु समय विस्तार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(अ) उक्त वर्गों के भू धृतियों द्वारा विनियमितीकरण का आदेश कराकर यदि शुल्क/नजराना की प्रथम किश्त इस शासनादेश की निर्गमन तिथि से 06 माह की अवधि के अन्दर जमा की

जाती है तो ऐसे भू धृतियों को वर्ष 2000 के सर्किल रेट के आधार पर शुल्क/नजराना देय होगा। इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 06 माह की अवधि में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित नजराना/शुल्क की प्रथम किश्त जमा न होने की स्थिति में शुल्क/नजराना जमा करने की तिथि को प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर ही देय नजराना/शुल्क की गणना की जायेगी। पूर्व में जमा किये गये शुल्क को समायोजित किया जायेगा। उक्त संशोधन के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत शासनादेश में निहित व्यवस्था एवं उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(ब) इन शासनादेशों के समयबद्ध प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारीगण समस्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों को पंजीबद्ध करायेंगे एवं शिविरों के माध्यम से भी समयवद्धता के दृष्टिगत निस्तारण करायेंगे।

(स) शासनादेश प्रभावी रहने तक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्राप्त आवेदन एवं विनियमित किये गये प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना राजस्व परिषद् द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

(द) विनियमितीकरण हेतु प्रदर्श आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(ध) जिलाधिकारी प्रश्नगत भू-सुधार व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायेंगे।

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेशों एवं इस शासनादेश के अन्तर्गत विनियमितीकरण करने की समय-सीमा इस शासनादेश के निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष तक अर्थात् दिनांक 18 फरवरी, 2019 तक ही प्रभावी रहेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव

संख्या-301(1)/XVIII(II)/2018 एवं तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
- ✓ 7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, को तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

विनियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र

- 1- प्रासंगिक शासनादेशों का विवरण जिसके अन्तर्गत विनियमितीकरण चाहा गया है, का उल्लेख करें।
- 2- विनियमितीकरण किस भूमि की श्रेणी हेतु आवेदन किया जा रहा है -

(निम्न भूमि की श्रेणी में से सही क्रमांक पर ✓ को लगायें)

1. सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अन्तर्गत पट्टेदारों को आवंटित भूमि;
2. राज्य गठन के उपरान्त दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को आवंटित आवासीय भूमि सहित कृषि भूमि;
3. टिहरी बाँध विस्थापितों को आवंटित भूमि एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा आवंटित अनारक्षित वन भूमि;
4. जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के दमुवाढूंगा अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से अनारक्षित भूमि;
5. खाम स्टेट की भूमि;
6. जनपद ऊधमसिंहनगर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को तहसील सितारगंज के अन्तर्गत कल्याणपुर एवं अन्य ग्रामों में आवंटित भूमि;
7. अनुसूचित जाति/शिल्पकारों को हरि ग्रामों में आवंटित भूमि;
8. उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा-20 के अन्तर्गत सीर या खुदकाश्त के आसामियों को आवंटित भूमि;
9. संरक्षित वन भूमि से अधिसूचित गैर वनाच्छादित/अनारक्षित क्षेत्र में आवंटित कृषि भूमि;
10. खनन, बाँध एवं जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि;

(3) आवेदक का नाम _____

(i) पिता/पति/संरक्षक का नाम _____

(ii) निवास स्थान _____

(iii) क. ग्राम/तोक/मौहल्ला/वार्ड _____

ख. विकासखण्ड का नाम _____

ग. तहसील का नाम _____

घ. जनपद _____

चित्र

(3) पुष्टि हेतु पट्टे/अभिलेख आदि संलग्नकों की सूची _____

(4) काबिज भूमि का खाता, खसरा एवं खतौनी की क्रम संख्या _____

(5) फसली वर्ष का विवरण _____

(6) खसरा, खतौनी में अवैध रूप से कब्जाधारक/पट्टेदार आदि के उल्लेख का विवरण _____

(7) काबिज भूमि की जोत का कुल क्षेत्रफल _____

(8) क्या खातेदार अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/बीपीओएल0 जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख _____

(9) कब्जे की अवधि की पुष्टि में प्रस्तुत अभिलेखों का विवरण _____

(10) खातेदार द्वारा मालगुजारी की देयता आदि का विवरण _____

(11) धृति से सम्बन्धित कोई आज्ञा/आदेश का संक्षिप्त विवरण _____

घोषणा

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, वह प्रमाणित है। प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में यदि कोई तथ्य असत्य/भ्रामक पाया जाता है तो उसका दायित्व अधोहस्ताक्षरी/आवेदक का होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

1. उप जिलाधिकारी की आख्या।
2. जिलाधिकारी का आदेश।
3. जमा की गयी शुल्क का विवरण।

जांच रिपोर्ट (यहां से आगे)